राज्य परीक्षाओं हेतु डेली करेंट अफेयर्स 21.08.2020

जागरूकता फैलाने के लिए "कोरोना फाइटर" गेम लॉन्च किया गया है।

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोरोना फाइटर्स नामक इस प्रकार का पहला इंटरैक्टिव अत्याधुनिक गेम लॉन्च किया है। यह प्रमुख कोविड उपयुक्त व्यवहारों के आग्रह का पालन करने के लिए किया गया है।
- यह गेम कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है।
- इस गेम को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाता रहे।
- व्यवहारिक परिवर्तन को शामिल करने के लिए इस प्रकार की पहलें अतीत में भी शुरू की गई थीं, उदा. पोलियो अभियान, जो लोगों की भागीदारी और समर्थन और कई फिल्म उद्योग के पेशेवरों के योगदान के माध्यम से एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया था।

इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है।

- मध्य प्रदेश का इंदौर, देश के 4,242 शहरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है।
- भोपाल को शीर्ष-10 में शामिल करने के साथ सर्वश्रेष्ठ स्व-स्थायी राजधानी के रूप में चुना गया है। भोपाल शहर पिछले वर्ष 19वें स्थान पर था। अब भोपाल सातवें स्थान पर है।
- सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक शहरी निकायों के साथ मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्रदान किया गया है।
- मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार मिले हैं।
- पिछले वर्ष बुरहानपुर को 103वां स्थान मिला था। इस वर्ष इसे सबसे तेजी से प्रगति करने वाले शहर का पुरस्कार मिला है।
- जबलपुर को नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया में देश के सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है।
- इस श्रेणी में रतलाम नगर निगम को नागरिक प्रतिक्रिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह उल्लेखनीय है कि पिछले तीन सर्वेक्षणों में, मध्य प्रदेश के 20 शहर देश के शीर्ष 100 शहरों में शामिल रहे हैं।

कमला हैरिस, पहली भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है।

- अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अपना नामांकन स्वीकार कर लिया है।
- कमला देवी हैरिस, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने वर्ष 2017 से कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर के रूप में काम किया है। अब, वह 2020 के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं।

बांग्लादेश ने 100% टैरिफ लाइनों के लिए 'टैरिफ-मुक्त कोटा मुक्त' पहुंच प्रदान की है।

- भारत ने वर्ष 2011 से साफ्टा के अंतर्गत बांग्लादेश के लिए अपने विशाल बाजार खोले हैं, जिससे बांग्लादेश के निर्यातकों को शराब और तम्बाकू को छोड़कर 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के लिए टैरिफ मुक्त और कोटा मुक्त (डी.एफ.क्यू.एफ.) बाजार पहुंच की अनुमति प्रदान की गई है।
- बांग्लादेश के निर्यात ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 42 प्रतिशत से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।
- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की मुक्त व्यापार व्यवस्था है।
- यह समझौता वर्ष 2006 में लागू किया गया था, जिसने 1993 सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था का स्थान लिया था।
- साफ्टा के हस्ताक्षरकर्ता देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं।

ट्राईफूड परियोजना

- जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 'ट्राइफूड' परियोजना के अंतर्गत वर्चुअल रूप से तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया है।
- ट्राइफूड परियोजना का उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र की गई अप्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय को बढ़ाना है। 'ट्राईफूड' परियोजना को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना के अंतर्गत, दो अप्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- ट्राइफेड, आदिवासियों के उत्थान के लिए नोडल एजेंसी के रूप में इस अभूतपूर्व समय में उनके संकट को कम करने के लिए कई पहलें शुरू कर रहा है।
- इस पहल का उद्देश्य इन दोनों राज्यों में जनजातीय आबादी के लिए बहुत सारे लाभ लाना है।

महाराष्ट्र में एन.ई.पी. कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु समिति

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
- चूंकि राज्य की शिक्षा नीति में आवश्यक और अनिवार्य बदलावों को अपनाने से पहले नई नीति पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त, सभी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ और शोधकर्ता तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, छात्र-उन्मुख शिक्षा आदि के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समिति में शामिल होंगे।
- राज्य में उपलब्ध ऑफ़लाइन और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा विभाग उत्तरदायी होगा।